



CV
26/7/86

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दर्ज 2, 1986/वैशाख 12, 1908

N o. 4]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 1986/VAISHAKHA 12, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती हैं जिससे कि यह असाधारण संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

रक्षा मंत्रालय

प्रधिकारी

नई दिल्ली, 2 मई, 1986

का.नि.सं. 4 (ग्र.)—केंद्रीय सरकार, तटरक्षक प्रधिनियम, 1978 (1978 का 30) की व्यापारा 123 के उपचारा (2) के छंड (क), (घ), (इ) (ब), (ट) और (ठ) के साथ पठित उपचारा (1) व्यापार प्रस्तुत जाहिनर्यों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है,
प्रथम—

पठ्याय—।

प्रारंभिक

1. नियम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का मंजिल वाम, तटरक्षक (साधारण) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रयुक्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रयोगित न हो—

(क) “प्रधिनियम” से तटरक्षक प्रधिनियम, 1978 (1978 का 30) प्रसिद्ध है।

(ब) “उपचार” में इन नियमों से सतत उपचार व्याप्ति है,

(ग) “बोर्ड” से नियम 36 के अधीन संयोजित जांच बोर्ड प्रसिद्ध है,

(घ) “तटरक्षक व्यवेश” से तटरक्षक महानिवेशक द्वारा जारी किया गया व्यवेश प्रसिद्ध है,

(इ) “तटरक्षक शेत्र” से नियम 4 के उपनियम (3) में विनियिष्ट कोई तटरक्षक शेत्र प्रसिद्ध है,

(च) “कार्यपालक प्रधिकारी” से कोई ऐसा प्रधिकारी प्रसिद्ध है जो पीत के कार्यपालक कर्तव्यों का निष्पादन करता है,

(छ) “वैदेशीय कामांडर” से नियम 4 के उपनियम (2) में विनियिष्ट कामांडर तटरक्षक शेत्र, प्रसिद्ध है,

(ज) उन शब्दों और पर्वों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही प्रथा होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. रिपोर्ट और आवेदन—इन नियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी तटरक्षक प्रधिकारी को की जाने वाली कोई रिपोर्ट या आवेदन, उचित प्रणाली के माध्यम से लिखित रूप में किया जाएगा, जब तक कि उक्त प्रधिकारी सेवार्थों को अत्यावश्यकताओं के कारण या अन्यथा लैखन से प्रसिद्धि न हो दे।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री

संगठन

रेकर्ड और समरेशन

4. तटरक्षक का गठन—(1) तटरक्षक में अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, नायिक और तटरक्षक सेवा में नियुक्त या अध्यावेशित अन्य प्रधावेशित व्यक्ति होंगे।

(2) महानिदेशक निम्नलिखित प्रधिकारियों के भाइयम से समावेशन करेगा—

(क) कमांडर, तटरक्षक थेव, परिवर्ग,

(ख) कमांडर, तटरक्षक थेव, पूर्व

(ग) कमांडर, तटरक्षक थेव, अद्यमान और निकोबार द्वीप, और

(घ) कमांडर, तटरक्षक थेव-शूल्क

(3) (क) तटरक्षक थेव, परिवर्ग में शौदीयज्ञेत्र और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल राज्यों और गोवा, दमण और दीप तथा लकड़ीप के संभ राज्य जैवों के तटीय जैवों के साथ-साथ भारत के सामुद्रिक थेव समाविष्ट होंगे,

(ख) तटरक्षक थेव, पूर्व में तटीय थेव और तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, परिवर्ग वंशाल राज्यों और पांडवेरी संभ राज्य थेव के तटीय जैवों के साथ-साथ भारत के सामुद्रिक थेव समाविष्ट होंगे,

(ग) तटरक्षक थेव, अद्यमान और निकोबार द्वीप, में तटीय थेव अद्यमान और निकोबार द्वीप संभ राज्य थेव के तटीय जैवों के साथ-साथ सामुद्रिक थेव समाविष्ट होंगे।

(घ) कमांडर, तटरक्षक थेव-शूल्क, महानिदेशक द्वारा उसे सौंपे गए सभी प्रार्थी पर संक्रियात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण करेगा।

5. प्रत्येक तटरक्षक थेव को जिलों में भी विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक जिला महानिदेशक द्वारा मियुक्त किए जाने वाले जिला कमांडर के पर्वतेश्वर के अधीन होंगा।

6. महानिदेशक, समय-समय पर देवा की मावश्यकताओं पर निर्भर रहते हुए, उन्होंने संभा में रुटेशन स्थापित करेगा और उन्होंने संभा में प्रत्येक तटरक्षक थेव/जिला/स्टेशन को मौजिगा जिला वह उचित समझे।

9. विशेषज्ञता—अधिकारी और अध्यावेशित व्यक्ति निम्नलिखित रूप में विशेषज्ञता के पास होंगे, अर्थात्—

कामिक के प्रवर्ग	विशेषज्ञता	प्रधर विशेषज्ञता
(क) (1) अधिकारी (सामारण फर्मेंट)	पाइलट नोवोलक विधि प्रयुषण नियंत्रण उदारण पोताक्षरी	लागू नहीं होता
(2) अधिकारी (तकनीकी)	विधानन इंजीनियरी विद्युत इंजीनियरी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी प्रदूषण नियंत्रण उदारण पोताक्षरी समृद्धि इंजीनियरी	लागू सभी होता

(ख) (१) अधीनस्थ अधिकारी और नायिक (साधारण कर्तव्य)	नायिक मंत्रिमणि	(१) तोपची मेट स्टार्टर मास्टर सेटिंगो आपरेटर वायुसीनिक गोताबोर इंजीनियरी वायु हंजीनियरी विषुत वायु विषुत वायु रेडियो
(२) अधीनस्थ अधिकारी और नायिक (तकनीकी)	गम्भीर इंजीनियरी वायु हंजीनियरी विषुत इंजीनियरी वायु विषुत इंजीनियरी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी वायु इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी हल इंजीनियरी	लग्न नहीं होता
(३) अधीनस्थ अधिकारी और नायिक (आन्तरिक)	पूर्णि महायक रसोदाया स्ट्रॉबे	लग्न नहीं होता

10. नटरक्षक पोतों का समावेशन—(१) नटरक्षक पोतों, जलयान वायुयानों या ऐसे स्थानों के, जो महानिवेशक द्वारा प्रयोगायित किए जाएं, समावेशन को संकीर्णात्मक समावेशन समझा जाएगा।

(२) साधारणतः साधारण कर्तव्य प्राप्ति के अधिकारी या अभ्यावेशित अधिकारी, संकीर्णात्मक समावेशन करेगा या किसी ऐसे कार्य प्राप्तकर्म को निर्धारित करेगा जिसमें नटरक्षक सेवा की विभिन्न शाखाओं का सहयोग अन्वेषित है। इसे अन्य अधिकारियों और अभ्यावेशित अधिकारियों को महानिवेशक द्वारा नियुक्ति या निवेश द्वारा प्रदत्त किया जा सकेगा।

(३) पोतों/जलयानों/वायुयान का समावेशन, साधारण कर्तव्य प्राप्ति के अन्तर्गत अधिकारियों और नायिक विशेषज्ञ वाले अभ्यावेशित अधिकारियों तक सौमित्र रहेगा, सिवाय तब के जब उसे वर्गित प्राधिकारी द्वारा प्रयोगता और प्राप्तकर्म द्वारा अन्तिम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त कर्तव्यप्राप्ति योग्यता दी जाएगी।

(४) नटरक्षक पोतों/जलयानों, स्थानयानों और वायुयानों का समावेशन नटरक्षक के लिए तैनाती के दौरान भारतीय नौसेना के अधिकारियों और नायिकों द्वारा भी, जब उन्हें महानिवेशक द्वारा विनिर्दिष्ट नियुक्ति किया जाए, किया जाएगा।

(५) नटरक्षक पोतों के समावेशन में नियुक्त तकनीकी अधिकारी, समावेशन के ऐसे कृत्य कर सकेंगे जो उनके कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए आवश्यक हैं।

(६) सरकार के नागरिक विभागों के अधीन नियुक्तियों करने वाले अधिकारी, महानिवेशक के स्पष्ट प्रावेशों के बिना, उनके संबंधित विभागों में उनके अधीन सेवा कर रहे अधिकारियों और अभ्यावेशित अधिकारियों से विशेष नटरक्षक के कार्यकर पर कोई समावेशन नहीं करेंगे या उन्हें कोई आदेश जारी नहीं करेंगे।

11. समावेश करने वाला अधिकारी—रैक और प्रगता—नटरक्षक पोतों की समावेश करने वाले अधिकारी, सभी अवसरों पर, चाहे वे तट पर हों या जल पर, उनके समावेशन के अधीन रखे गए अधिकारियों के छार रैक और प्रगता लेंगे।

12. कमान अधिकारी को अस्याई प्राप्तिस्थिति में समावेशन—किसी तट स्थापन को छोड़कर, (स्टाफ या विशेष कार्य के लिए) अतिरिक्त रूप में

नियुक्ति किसी अधिकारी या किसी नेत्रे नियोजित वायुयानों का समावेशन करने के लिए अद्वित नहीं है, से विशेष करके पर अव्यैष्ट साधारण कर्तव्य अधिकारी, कमान अधिकारी को अस्याई प्राप्तिस्थिति में, कमान अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य धारण करेगा, किसी तट स्थापन, में समावेशन, कमान अधिकारी की शक्ति द्वारा प्राप्त हो जाएगा। यदि कमान अधिकारी की शक्ति का कोई अधिकारी अपस्थित न हो तो, समावेशन, उपस्थिति उपर्युक्तम् अधिकारी को न्यायित हो जाएगा, किसी समावेशन, स्टाफ या विशेष कार्य के लिए या चर्याओं के लिए अतिरिक्त रूप में नियुक्त किसी अधिकारी को न्यायित नहीं होता।

13. निगरानी—अधिकारी का प्राधिकार—उप भास्त्रानिरोक्तक के रैक से नीचे का प्रत्येक अधिकारी (जो तटस्थ पोत का कार्यपालक अधिकारी या कमान अधिकारी नहीं है) और अभ्यावेशित अधिकारी, उन कर्तव्यों, जिनका भास्त्रानिरोक्त उस पर है, के पालन के संबंध में, निगरानी अधिकारी के बाहे, उसका रैक कोई भी हा, अधिनस्थ होता।

14. विशेष प्रकार अधिकारी और अभ्यावेशित अधिकारी द्वारा दी जाएगी—

(१) जब या तट पर सेवा कर रहे अधिकारी या अभ्यावेशित अधिकारी, उस पाँत या स्थापन या स्टेशन की, जिसमें वे सेवा कर रहे हैं या जिससे वे मंत्रजन हैं, पुस्तकों में ज्ञान हुए होंगे।

(२) जब ऐसा आहा गया है कि स्टाफ या विशेष कार्य के लिये अतिरिक्त रूप में धारित किसी अधिकारी को, पोत संभालने, और उसी प्रकार के कार्य में अभ्यास या अनुभव प्राप्त करना चाहिये तो उसे सम्बूद्ध या अंदरगाह में निगरानी का भास्त्रानिरोक्त ग्रहण करने का प्राधिकार कमान अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा; परन्तु इस नियम की बोई भी बात, उसे समावेशन के उपसाधिकार की पवित्रि में नहीं रखेगी।

15. प्रोत्तर किया गया प्रविकारी—बोई ऐसा अधिकारी, जिसे प्रोत्तर किया गया है पूर्ण कर्तव्य करने के लिये प्रतिनियुक्त किये गये प्रविकारी, विधि व अधिसंघ के रूप में ब्रारित हैं, वही रैक और समावेशन ग्रहण

16. प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी—सभी प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य पोत के वलक पर कर्तव्य करने के लिये प्रतिनियुक्त किये गये प्रविकारी, विधि व अधिसंघ के रूप में ब्रारित हैं, वही रैक और समावेशन ग्रहण

करेंगे, तथा वे जिस प्रकार नियोजित हैं उस समय के लिये प्रत्येक वार्षिक वार्षिक सभी समझे जायेंगे, मानो वे बस्तुतः कमिं-मण्डल के थे।

17. याक्षा करने वाले अधिकारी—किसी तटरक्षक पोत में याक्षा करने वाले किसी अधिकारी को, यद्यपि वह अधिसंघ के रूप में वार्षिक है, उस दशा में कर्तव्य करने के लिये आवेदन दिया जा सकेगा, यदि वह उस पोत, जिस पर वह अब बढ़ा है, के कार्यपालक अधिकारी के रैंक से ऊपर या कमिं रैंक का है। इस प्रकार नियोजित के दौरान वह वही रैंक और समादेशन ग्रहण करेगा, तथा प्रत्येक वार्षिक वर्ष वही समझा जायेगा मानो वह बस्तुतः कमिं-मण्डल का था। पोत के कमात् अधिकारी की मृत्यु की बशा में, उसका कार्यकारी समादेशन नियम 12 में धृष्टि अधिकारियों में निहित हो जायेगा और महानिवेशक के साप्त प्राधिकार के सिवाय किसी भी दशा में किसी अधिसंघ अधिकारी द्वारा वार्षण नहीं किया जायेगा।

18. सेना, नौसेना, और वायु सेना के अधिकारियों का प्राधिकार—तटरक्षक पर नियुक्त सेना, नौसेना और वायुसेना के किसी अधिकारी को ऐसी तब अधिकारियों होंगी और वह ऐसी तब अधिकारियों का प्रयोग करेगा जो तत्समान रैंक के या तत्समान नियुक्त धारण करने वाले तटरक्षक के किसी अधिकारी में निहित होती है या उसके द्वारा प्रयोग की जायें।

19. अधिनियम की धारा 57 और धारा 58 के उपकर्णों के अधीन रहते हुए, जब अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को किसी निकाय से संलग्न किया जाता है, या वह किसी घूनिट में सेवा कर रहा है, या उस नियमित सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अस्पताल में रोगी के रूप में वार्षिक किया जाता है तो ऐसे निकाय, घूनिट या अस्पताल का कमात् अधिकारी, ऐसे अधिकारियों पर, जो रैंक में उससे कमिं हैं, समादेशन की सभी अधिकारियों का और महानिवेशक कामिंक पर समादेशन और वर्ष की सभी अधिकारियों का प्रयोग करेगा।

प्रध्याय 4

सेवानिवृत्ति, परम्परा, सेवा से हटाया जाना, सेवोन्मुक्ति या सेवा से निर्मुक्ति

20. सेवानिवृत्ति (1) कमांडेंट के रैंक से उच्चतर कोई रैंक धारण करने वाले अधिकारियों के लिये सेवानिवृत्ति की आयु धारावत वर्ष होगी और अन्य रैंकों के अधिकारियों के लिये वह पचपन वर्ष होगी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार—

(क) कमांडेंट के रैंक से उच्चतर रैंक के किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति आयु किसी भी समय एक वर्ष भी अवधि के लिये बढ़ा सकेगी, किन्तु किसी भी दशा में साठ वर्ष की आयु से अधिक नहीं बढ़ा सकेगी,

(ख) प्रथ्य रैंकों के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति-आयु किसी भी समय एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ा सकेगी, किन्तु किसी भी दशा में धारावत वर्ष की आयु से अधिक नहीं बढ़ा सकेगी।

(2) अधीनस्थ अधिकारियों और नाविकों की सेवानिवृत्ति-आयु पचपन वर्ष होगी।

21. परम्परा, सेवा से हटाया जाना, सेवोन्मुक्ति या सेवा में निर्मुक्ति

(1) स्तम्भ 1 में विनिविष्ट प्राधिकारी, स्तम्भ 2 में विनिविष्ट तटरक्षक के सदस्यों की परम्परा, सेवा से हटाये जाने, सेवोन्मुक्ति या सेवा से निर्मुक्ति को, इससे उपाध्याय सारणी के स्तम्भ 4 में विनिविष्ट प्रक्रिया के अनुसार, स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विवरणित धारारों पर, प्राधिकृत करने के लिये सक्षम होंगे। इस नियम द्वारा पूर्णतः प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का उससे वरिष्ठ किसी प्रथ्य प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा।

पारणी

सर्वम् प्राधिकारी तटरक्षक का सरवस्य प्राक्षात् जिन पर सेवा समाप्त की जा सकती है सेवा की समाप्ति के लिए प्रक्रिया

1	2	3	4
केन्द्र सरकार	अधिकारी	(1) प्रवचार (2) अनुप्रृक्तता (3) प्रशिक्षण में असंतोषप्रद प्रगति (4) भर्ती के समय निष्पाय/गलत जानकारी देना (5) अस्वस्थता के आवार पर प्रयोग्यता (6) मपने अनुरोध पर	नियम 22 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार नियम 22 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार नियम 24 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 25 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 26 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 27 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 23 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 23 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार नियम 24 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 25 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 26 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार। नियम 27 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार।
महानिवेशक	अधीनस्थ अधिकारी और नाविक	(1) प्रवचार (2) अनुप्रृक्तता (3) प्रशिक्षण के दौरान प्रसंतोषप्रद प्रगति (4) भर्ती के समय निष्पाय/गलत जानकारी देना (5) अस्वस्थता के आवार पर प्रयोग्यता (6) मपने अनुरोध पर	(2) जब, प्रधिकारी के प्रवचार की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात्, महानिवेशक का यह समाधान हो जाता है कि किसी तटरक्षक अधिकारी का विचारण समीक्षा या साध्य नहीं है और उसकी वह राय है कि अधिकारी को सेवा में और रखना बाढ़नीय नहीं है, तो महानिवेशक, अधिकारी को उसके प्रतिकूल सभी रिपोर्टों के साथ इस प्रकार सुवित करेगा और उससे उसका स्पष्टीकरण तथा प्रतिवाद लिखित रूप से प्रस्तुत करने की मांग की जायेगी।

परन्तु महानिवेशक, केन्द्रीय सरकार की पूर्व धन्योदयन से, किसी ऐसी रिपोर्टों या उनके भाग को प्रकट करने से उस दशा में रोक सकेगा, यदि उसका प्रकरण राय की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(3) महानिवेशक द्वारा अधिकारी के स्पष्टीकरण को असमाधानप्रद समझे जाने की दशा में, या जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा विविष्ट किया

22. अधिकारियों की परम्परासेवा से हटाये जाने की प्रक्रिया—
(1) जब किसी अधिकारी की धारा 11 के अधीन पदम्पत्त फर्जे/सेवा से हटाये जाने का प्रस्ताव किया गया है तो उसे उपनियम (2) में विनिविष्ट रीति से हेतुक वित्त करने का अवसर दिया जायेगा।

परन्तु यह उपनियम नहीं लागू वहा होगा—

(क) जहाँ अधिकारी को ऐसे प्रवचार के प्रधार पर परम्परा/किया गया सेवा से हटाया गया है जिस पर वर्ष न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्ध की गई है।

(ख) जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसे कारणों से जो लेखांक किये जायेंगे, अधिकारी को हेतुक वित्त करने का अवसर देवा समीक्षा या पुनिप्रृक्तता रूप से साध्य नहीं है।

जाये, तब मामले को, अधिकारी के प्रतिवाद और अधिकारी की सेवा समाप्त करने के बारे में महानिरीक्षक की सिफारिश सहित, उपनियम (5) में विनियिष्ट रीति से सरकार के पास प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) जहाँ, किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी की दोषसिद्धि पर, केन्द्रीय सरकार या महानिरीक्षक यह समझता है कि अधिकारी के उस आचरण से, सेवा में उसे और रखना घटाऊंगी जो गया है जिस पर उसकी दोषसिद्धि की गई है, वहाँ उसे दोषसिद्धि करने वाले दण्ड न्यायालय के नियम की एक प्रमाणित प्रतिलिपि, अधिकारी की सेवा की समाप्ति के बारे में महानिरीक्षक की सिफारिश सहित, उपनियम (5) में विनियिष्ट रीति से केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत की जायेगी।

(5) जब उपनियम (3) या (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार के पास कोई मामला प्रस्तुत किया जाये, तब महानिरीक्षक अपनी यह सिफारिश करेगा कि क्या अधिकारी की सेवा समाप्त की जाये और यदि हो तो, क्या अधिकारी को—

(क) पदब्युत कर दिया जाये; या

(ख) सेवा से हटा दिया जाये।

(6) केन्द्रीय सरकार, रिपोर्टों और यथास्थिति, अधिकारी के प्रतिवाद, यदि कोई हो, या दण्ड न्यायालय के नियम और महानिरीक्षक की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, अधिकारी को पदब्युत कर सकती या सेवा से हटा सकती।

(7) जब महानिरीक्षक का यह समाधान हो गया है कि कोई अधिकारी अनुपयुक्त के आधार पर सेवा में रखे जाने के लिये अद्योत्तम है, तो वह अधिकारी को अपनी मामला स्वल्प करने का अवसर देने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार को यह सिफारिश कर सकता है कि अधिकारी की सेवा समाप्त की जाये। महानिरीक्षक, केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशों के लिये कारण और अधिकारी की सेवा का अधिसंबंध भी देंगे:

परन्तु जहाँ राज्य की सुलगा के हित में, अधिकारी को अपना यामला स्वल्प करने का अवसर देना असमिक्त होगा, वहाँ केन्द्रीय सरकार के लिये यह विविध पूर्ण होगा कि वह, अधिकारी को अपना यामला स्वल्प करने का अवसर दिये बिना, अधिकारी की सेवा समाप्त करने का आदेश पाठित करे।

(8) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (7) के अधीन रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, अधिकारी को पदब्युत करने या सेवा से हटाये जाने का ऐसा आदेश पाठित कर सकती जो वह उचित समझे।

(9) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (8) में, अधिकारी को पेंशन या उपबोन सहित या उसके बिना, सेवा निवृत्त कर सकती या सेवा से हटाये जाने की प्रक्रिया—

(1) जहाँ कमान अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी अधिकारी को, अवचार या अनुपयुक्तता के आधार पर सेवा में रखे रहना अनुपयुक्त समझा गया है, वहाँ वह, तटरक्षक मुख्यालय में महानिरीक्षक को तटरक्षक से ऐसे अधिकारी को पदब्युत करने सेवा से हटाये जाने की सिफारिश कर सकता।

(2) किसी अधिकारी को पदब्युत करने सेवा से हटाये जाने की सिफारिश के सभी मामलों में, कमान अधिकारी यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करेगा कि अधिकारी को उपयुक्त बेतावनी और सुधरने के लिये पर्याप्त समय दिया गया है। सिफारिश के साथ इस आशय का वस्तावेजी साक्ष्य होगा।

(3) जहाँ, किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी को सिद्धांदाय छहराये जाने पर, वह उप महानिरीक्षक, जिसके अधीन वह अधिकारी सेवा कर रहा है, वह समझता है कि अधिकारी को ऐसे आचरण से, जिनप्रे आधार पर उसे सिद्धांदाय छहराया गया है, उसे सेवा में और रखे रहना

अवांछित है, वहाँ दण्ड न्यायालय के उसे दोषसिद्ध करने वाले नियम की एक प्रमाणित प्रति, उस उपमहानिरीक्षक के, जिसके अधीन वह अधिकारी सेवा कर रहा है, उपनियम (4) में विनियिष्ट रीति से अधिकारी की सेवा समाप्त करने से संबंधित सिफारिशों के साथ तटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक के ममक प्रस्तुत की जायेगी।

(4) तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक, उपनियम (1) या (3) के अधीन किसी सिफारिश के प्राप्त होने पर, संबंधित अधिकारी पदब्युत करने या सेवा से हटाये जाने का आदेश पाठित कर सकता।

(5) तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक, उपयुक्त मामलों में, अधिकारी को, पेंशन या उपबोन सहित या उसके बिना, सेवा निवृत्त कर सकता। या सेवा से हटा सकता।

24. प्रशिक्षण में असंतोषप्रद प्रगति के आधार पर सेवान्मुक्त/सेवा से निर्मुक्त की प्रक्रिया—(1) जब तटरक्षक के किसी सदस्य को प्रशिक्षण में असंतोषप्रद प्रगति के कारण सेवान्मुक्त/सेवा से निर्मुक्त करने का प्रस्ताव है, तो उस प्रशिक्षण स्थापन का, जहाँ अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, कमान अधिकारी यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या तटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक को, अधिकारी की सेवा से निर्मुक्त के लिए सिफारिश कर सकता।

(2) किसी अधिकारी की सेवान्मुक्त या सेवा से निर्मुक्त के लिए की गई सिफारिशों के सभी मामलों में, प्रशिक्षण स्थापन का कमान अधिकारी यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करेगा कि अधिकारी को उपयुक्त चेतावनी और प्रगति दिखाने का पर्याप्त समय दिया गया है। सिफारिश के साथ इस आशय का वस्तावेजी साक्ष्य होगा।

(3) पदाल्पिति, केन्द्रीय सरकार या तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक उपनियम (1) के अधीन सिफारिश के प्राप्त होने पर, संबंधित अधिकारी को सेवान्मुक्त या सेवा से निर्मुक्त कर सकता।

25. भर्ती के रामय मिथ्या/गलत जानकारी देने के आधार पर सेवान्मुक्त/सेवा से निर्मुक्त की प्रक्रिया:

यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक, अधिकारी पदब्युक्त उपनियम के अधीन सिफारिश के प्राप्त होने पर, संबंधित अधिकारी को सेवान्मुक्त या सेवा से निर्मुक्त कर सकता।

26. मस्तवत्ता के कारण अवांशिकता के आधार पर सेवा निवृत्त/सेवा से निर्मुक्त/सेवान्मुक्त:

(1) जब अधिकारी कोई अधिकारी सामस्त बल विकित्सा सेवा विनियमों के अधीन गठित किसी विकित्सा बोर्ड द्वारा तटरक्षक सेवा के लिए स्पष्ट रूप से अव्योग्य पाया जाता है, तो उसे इस वियम में अधिकारीषित प्रक्रिया के अनुसार सेवानिवृत्त, सेवा से निर्मुक्त, या सेवान्मुक्त किया जा सकता।

(2) विकित्सा बोर्ड के अव्योग्य, विकित्सा बोर्ड के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात्, कि अधिकारी सेवा के किसी भी रूप के लिए स्पष्ट रूप से अव्योग्य है, तटरक्षक एक सूक्ष्मा जारी करेगा, जिसमें उस रोग या निःशक्तता की प्रकृति विषये वह प.डिट है और विकित्सा बोर्ड का निष्कर्ष विनियिष्ट होता तथा उसे वह भी सूचित करेगा कि निष्कर्ष को देखते हुए उसे सेवानिवृत्त, सेवा से निर्मुक्त या सेवान्मुक्त किया जा सकता है:

परन्तु जहाँ विकित्सा बोर्ड की राय में अधिकारी किसी मनोसक रोग से पीड़ित है और उस अधिकारी को उस रोग या निःशक्तता की प्रकृति के बारे में समूचित करना अनुरोध है या अधिकारी अपना हित समझने में अव्योग्य है, वहाँ रोग या निःशक्तता की प्रकृति अधिकारी के उम निकट नभूदी को जिसे उपनियम (3) के अधीन अभी देने का निष्कार होता है, निर्मुक्ति की जाएगी।

(3) ऐसी सूचना में यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि व्यक्ति सूचना की प्राप्ति की तारीख से पहले ही इन के भीतर, चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों के विरुद्ध चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष को अर्जी दे सकेगा।

(4) यदि कोई अर्जी उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दी जाती है तो व्यक्ति को, अधिकारियों की वजा में केंद्रीय सरकार द्वारा और अभ्यावेशित व्यक्तियों की दशा में तटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक द्वारा, उस आशय के आदेश द्वारा, सेवा निवृत्ति/सेवा से निर्मुक्त या सेवोन्मुक्त किया जा सकेगा।

(5) यदि कोई अर्जी उपनियम (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर वी जाती है तो अध्यक्ष, चिकित्सा बोर्ड, उसे संबंधित व्यक्तियों के ग्राहीन गठित चिकित्सा बोर्ड (अपील) के पास उस अर्जी पर उसके विनियम के लिए विनिर्दिष्ट करेगा। मामले से संबंधित अभियोगों के साथ चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों, सटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक को भेजे जाएंगे। यदि दोनों चिकित्सा बोर्डों के निष्कर्षों में कोई मतभेद न हो तो व्यक्ति को, अधिकारियों की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा और अभ्यावेशित व्यक्तियों की दशा में तटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक द्वारा, उस आशय के आदेश द्वारा, सेवा निवृत्ति/सेवा से निर्मुक्त या सेवोन्मुक्त किया जा सकेगा।

(6) किसी चिकित्सा बोर्ड और चिकित्सा बोर्ड (अपील) के निष्कर्षों में मतभेद होने की दशा में, अधिकारियों के ग्राहीन में महानिरीक्षक या अभ्यावेशित व्यक्तियों के मामले में तटरक्षक मुख्यालय में महानिरीक्षक मामले को, मंत्रालय व्यक्तियों के ग्राहीन उस प्रयोगजन के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड (पूर्णविलोकन) के पास अस्थायता के कारण अधीक्षित के आधार पर उस व्यक्ति को सेवा निवृत्ति/सेवा से निर्मुक्त या सेवोन्मुक्त करने से पूर्ण राय के लिए भेजेगा।

27. अपने अनुरोध पर सेवोन्मुक्ति, सेवा से निर्मुक्ति या सेवानिवृत्ति वी प्रविया —

(1) तटरक्षक का कोई सदस्य, आपवाहिक मामलों में, अर्थात् अनुकूल के आधारों पर, अर्थात् ऐसे मामलों में जहाँ यह स्पष्ट हो कि निःसंदेह तात्परिक कलिनाई तटरक्षक के सदस्य या उसके कुटुम्ब के सदस्यों वाले सेवा में उसके रवै रहने से होगी, अपनी सेवोन्मुक्ति, सेवा से निर्मुक्ति या सेवा निवृत्ति अभिलास से कर सकेगा।

(2) केंद्रीय सरकार, किसी मामले की परिस्थितियों का व्याप रखने हुए, सेवानिवृत्ति की ग्राह्य अभिप्राप्त करने से पहले अधिकारी की सेवोन्मुक्ति सेवा से निर्मुक्ति या सेवानिवृत्ति अनुज्ञात कर सकेगा। सेवोन्मुक्ति, सेवा से निर्मुक्ति या सेवानिवृत्ति का प्रयत्न केंद्रीय सरकार के भीतर का मामला होगा।

(3) तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक, किसी अधिकारी से भिन्न तटरक्षक के किसी सदस्य को अनुकूल के आधारों पर सेवोन्मुक्त, सेवा से निर्मुक्त या सेवानिवृत्ति कर सकेगा।

(4) अनुकूल के आधार पर सेवोन्मुक्ति, सेवा से निर्मुक्ति या सेवानिवृत्ति के आवेदन को कमान अधिकारी द्वारा केंद्रीय कमांडर के माध्यम से तटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक को अप्रेषित किया जाएगा।

28. वह तारीख जिससे सेवा निवृत्ति/पदच्युती/सेवा से हटाया जाना/पदस्थान/सेवोन्मुक्ति प्रभावी होगी :

(1) अधिनियम के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति, पदच्युति, सेवा से हटाए जाने, पदस्थान या सेवोन्मुक्त की तारीख, यथास्थिति सेवानिवृत्ति, पदच्युती, सेवा से हटाए जाने, पदस्थान या सेवानिवृत्ति वाले आदेश में उस निमित विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी।

(2) अधिनियम के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति, पदच्युति, सेवा से हटाए जाना, पदस्थान या सेवोन्मुक्त भूलक्षणी महीं होगी।

प्रध्याय 5

विहित अधिकारी और प्राधिकारी

29. विहित अधिकारी और प्राधिकारी - नीचे को सारणों के संन्दर्भ (3) और (4) में अर्थित अधिकारों और प्राधिकारी, उन सारणों के संन्दर्भ (2) में अन्तिमित प्रयोगजनों के लिए संस्तुत (1) में उल्लिखित व्यावहारिकों के अधीन विहित प्राधिकारी होंगे :

अधिनियम की धारा	प्रयोगजन	विहित अधिकारी	विहित प्राधिकारी
1	2	3	4
धारा 8	शपथ विलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए, कोई अधिकारी	---	---
धारा 9	पदस्थान और पद से निकाले जाने के लिए	---	---
धारा 13(1)	उपचारा (1) के घंट (क), (ख) और (ग) के अधीन संगम, आदि बनाने के लिए लिए पूर्ण मंगूरी प्रदान करने के लिए	---	1. अधिकारियों के लिए केंद्रीय सरकार अभ्यावेशित व्यक्तियों के लिए तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक 2. अधिकारियों के लिए महानिरीक्षक अभ्यावेशित व्यक्तियों के लिए तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक
धारा 63(1)	तटरक्षक पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति अधिनियम के अधीन कार्यालयों प्रारंभ करने के लिए दंड व्यायालय या तटरक्षक व्यायालय के चुनाव का विनियमन करने के लिए	कमांडर केंद्रीय मुख्यालय	---
धारा 71	व्यायालय के अधीन कार्यालयों प्रारंभ करने के लिए दंड व्यायालय या तटरक्षक व्यायालय के चुनाव का विनियमन करने के लिए	वह कमान अधिकारी जिसके समावेश के अधीन ग्राम्यक्षेत्र सेवा कर रहा है	---
धारा 86(1)	पदमें, विवरणियों या अन्य वस्तुवेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए	निवेशक (कार्मिक) तटरक्षक मुख्यालय और माराठीक अधिकारी, नाविकों का अध्यर्थी	---
धारा 89	1. विहित चित्र के किसी व्यक्ति के विवाहण के संबंध में कार्यालयों करने के लिए	वह अधिकारी जिसने तटरक्षक मुख्यालय द्वारा मूल विवाहण के लिए आदेश दिया	---

	2	3	4
	2. विचारण में हाजिर होने के लिए स्वास्थ्य का प्रमाणन्पत्र		पारात्मकाना या सुरक्षित प्रमिलों के द्वारा स्थान का, जहाँ अवृत्ति सेवा गया है, विकितसा प्रधिकारी
धारा 97	मृत्यु से दण्डाधिक्षिट किए गए किसी अधिकारी की अंतिम अभिरक्षा का आदेश देने के लिए	यह कमान अधिकारी जिसके समावेश के घट्टीन अभियुक्त अवृत्ति सेवा कर रहा था।	---
धारा 99	मृत्यु के दण्डाधिक्षिट के निश्चानन के लिए निरेण देने के लिए	यह कमान अधिकारी जिसके समावेश के घट्टीन अभियुक्त सेवा कर रहा था।	---
धारा 100(1)	किसी सिविल कारायार में परिरोध के लिए यह कमान अधिकारी जिसने तटरक्षक भ्यायालय निरेण देने के लिए	यह कमान अधिकारी जिसके समावेश के घट्टीन अभियुक्त सेवा कर रहा था।	---
धारा 100(2)	किसी अवृत्ति के किसी सिविल कारायार में परिरोध के लिए बारंट जारी करने के अधिकारी।	इण्डाइश के अधीन अवृत्ति का कार्यपालक लिए	---
धारा 103	किसी सिविल कारायार के भार्याधिक प्रधि-दण्डाधिक्षिट के अधीन अवृत्ति वा कमान कारी को और दण्डाधिक्षिट करने या अधिकारी उसमें फेरफार करने वाले आदेश से मुक्त बारंट जारी करने के लिए	कमान	---

30. धारा 67 के प्रयोगन के लिए, लांबा (1) में वर्णित और स्टंड (2) में वर्णित रूपे धारण करने वाले प्राधिकारियों को, नीचे की सारणी के स्तर (3) में उल्लिखित सीमा तक दंड देने की शक्ति होगी :

सारणी

प्राधिकारी	रैक	यह सीमा जिस तक दंड दिया जा सकता है	
		1	2
1. कमान अधिकारी	सभी रैक	मरी बंड	(1) अस्थावेशित सभी अवृत्तियों के 45 घंटे तक छुट्टी मिंग करने के प्रथम अपराध के लिए बेतन और भत्तों का अपर्कर्तन।
2. कार्यपालक अधिकारी	(1) कमांडेन्ट	(2) नाविकों को 14 दिन में अनधिक अवधि के लिए अतिरिक्त कार्य और कवायद (ह्रौल)	(2) अस्थावेशित सभी अवृत्तियों की 30 दिन में अनधिक अवधि के लिए छुट्टी का रोका जाना।
	(3) उपकमांडेन्ट	(3) अस्थावेशित सभी अवृत्तियों की 36 घंटे तक छुट्टी मिंग करने के प्रथम अपराध के लिए बेतन और भत्तों का प्राकर्तन।	(4) अस्थावेशित सभी अवृत्तियों की 36 घंटा।
	(4) महायक कमांडेन्ट	(4) अस्थावेशित सभी अवृत्तियों के 36 घंटे तक छुट्टी मिंग करने के प्रथम अपराध के लिए बेतन और भत्तों का प्राकर्तन।	(1) नाविकों को 7 दिन में अनधिक अवधि के लिए अतिरिक्त कार्य और कवायद।
	(5) नियानी प्रधिकारी/ईनिक प्रधिकारी	(5) महायक कमांडेन्ट और उससे ऊपर	(2) अधीनस्थ प्रधिकारियों द्वारा अवृत्तियों की 15 दिन में अनधिक अवधि के लिए छुट्टी का रोका जाना।
			(3) अधीनस्थ प्रधिकारियों में फ्रैंट अवृत्तियों की अन्तर्वर्ता।
			(1) नाविकों को एक दिन के लिए अतिरिक्त कार्य और कवायद।
			(2) नाविकों की अन्तर्वर्ता।

31. शपथ या प्रतिक्रिया-लटकाक वा प्रस्त्रेक गतमध्ये, निम्नलिखित प्रणय में शपथ लेगा या प्रतिक्रिया और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।—

शपथ/प्रतिक्रिया का प्राप्त

मैं, क. ए. ईवर की शपथ लेता हूँ/मत्यन्तिष्ठा में प्रतिक्रिया करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के मध्यिकारी के प्रति सज्जी अद्वा और निष्ठा रखूँगा और ऐसा कि मैं कर्तव्य द्वारा आवश्यक हूँ, ईमानदारी से और बफादारी से लटकाक की सेवा करूँगा और वायू भूमि या समुद्र मार्ग से जहाँ कहीं भी से जाने का आवेदन मिलेगा, वहाँ जाऊँगा और मैं भारत के संघ के राज्यपति के मध्य समावेशों का और अपने उपरिस्थापित किसी अधिकारी के समावेशों का अपने जीवन जोखिम उठा कर भी पालन करूँगा ।

हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर

(शपथ दिलाने वाले व्यक्ति का नाम
और पदनाम)

अध्याय—६

शिकायत और अध्यावेदन

32. उच्चतर प्राधिकारियों को शिकायत—(1) यदि कोई अधिकारी या अध्यावेदित व्यक्ति यह समझता है कि उसे कोई बैयकिनक, अत्यावार, अन्याय या अन्य कुरा बताव सहन करना पड़ा है या उसके साथ किसी भी प्रकार से अनुचित रूप से बताव किया गया है या वह अपने कान्याण को प्रभावित करने वाला अध्यावेदन करना नाहता है या सेवा से बंबंधित कोई सुझाव देता है तो वह उसे अपने बरिष्ठ अधिकारी के द्वारा में लाएगा ।

(2) यह उस बरिष्ठ अधिकारी, जिसे अध्यावेदन दिया गया है, का कर्तव्य होगा कि वह उसे उपर्युक्त कार्रवाई के लिए उच्चतर प्राधिकारियों के पाम अध्येतर करें ।

(3) इन नियमों में उल्लिखित गतियों के सिवाय, बरिष्ठ अधिकारी/प्राधिकारी से प्रतिरोध मानने की कोई अन्य गति निषिद्ध है ।

33. शिकायत किसको की जाएगी—(1) यदि, शिकायतकर्ता, सटरकाक पोत का कोई कमान अधिकारी है, तो उसकी शिकायत निषिद्ध रूप में होगी और उसके अध्ययन वरिष्ठ अधिकारी को मंबंधित होगी ।

(2) यदि शिकायतकर्ता, लटकाक पोतों से किसी एक पोत में, सेवा करने वाला कोई अधिकारी है तो उसकी शिकायत मीडिक रूप से कमान अधिकारी को की जाएगी जिसके द्वारा कोई शिकायतकर्ता उस प्रयोजन के लिए कमान अधिकारी से अध्ययोक्तन करने के लिए, मीडिक अनुरोध करेगा । यदि शिकायतकर्ता कोई अधिकारी है तो ऐसा अनुरोध कार्यालय अधिकारी को मार्फत किया जाएगा और यदि शिकायतकर्ता विभाग का प्रधान है तो अनुरोध संघे कमान अधिकारी से किया जाएगा । यदि शिकायतकर्ता किसी विभिन्न विभाग में कार्य करने वाला कोई अधिकारी है, तो अनुरोध, प्रयमः विभाग के प्रधान में किया जाएगा ।

(3) यदि शिकायतकर्ता अध्यावेदित व्यक्ति है, तो उसकी शिकायत मानिक रूप से कमान अधिकारी को की जाएगी । कमान अधिकारी से अध्ययोक्तन करने का अनुरोध, शिकायतकर्ता के प्रभागीय या विभागीय अधिकारी का मार्फत कार्यालय अधिकारी से किया जाएगा । उसके पोत या उसके स्वापन से विवारित अन्यावेदित अधिकारी से अपनी शिकायत उस अधिकारी से करेगा जिनके समावेश में वह उस समय होगा ।

34. शिकायतकर्ता द्वारा पालन किए जाने वाले नियम—(1) कोई शिकायत, ऐसे तथ्यों के, जो शिकायत से संबंधित है, कान्यत तक और स्वयं शिकायतकर्ता के अधिकारित परिणामों तक सीमित होगी ।

(2) दो या अधिक अधिकारियों द्वारा मध्यस्थ शिकायत अनुशासन नहीं है। प्रत्येक अधिकारी अपना शिकायत स्वयं करेगा ।

(3) मौद्रिक रूप से या लिखित रूप से, शिकायत करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि—

(क) शिकायत में तथ्यों का कथन उसकी सर्वोत्तम ज्ञानकारी के अनुसार सत्य है, और,

(ख) शिकायत ऐसी भाषा में नहीं की गई है जो ग्राहित, प्रबोधापूर्ण या अनुशासन के लिए लाइसेंस है ।

35. शिकायत को किस प्रकार निपटाया जाएगा—(1) किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, कमान अधिकारी, या उसे प्राप्त करने वाला अन्य अधिकारी, संवर का यह समाधान कर सकता है कि शिकायत इन नियमों के अनुसार की गई है । उसके पश्चात् वह अपने विवेक का, जो उसे ठीक प्रतीत होने, प्रयोग करते हुए उसका निपटान करेगा और शिकायतकर्ता को अपने विनिश्चय के बारे में सूचित करवाएगा ।

2 यदि शिकायत प्राप्त करने वाला कमान अधिकारी या अन्य अधिकारी इस प्रकार की गई शिकायत का उपचार करने से इंकार कर देता है या उसका उपचार करने में असमर्थ है, तो शिकायतकर्ता अत्यावार, अन्याय या अन्य कुरा बताव सहन करना पड़ा है या उसके साथ किसी भी प्रकार से अनुचित रूप से बताव किया गया है या वह अपने कान्याण को प्रभावित करने वाला अध्यावेदन करना नाहता है या सेवा से बंबंधित कोई सुझाव देता है तो वह उसे अपने विवेक का, जो अनुरोध प्राप्त होने पर, कमान अधिकारी, या अन्य अधिकारी, शिकायतकर्ता को इस विषय पर पुनर्विचार करने के लिए 24 घंटे का समय देगा । उसके पश्चात् शिकायतकर्ता, अपनी शिकायत कमान अधिकारी या अन्य अधिकारी को लिखित रूप में देगा, जो बाद में शिकायत को उम पर अपनी टिप्पणी महित अगले बरिष्ठ अधिकारी को अधेष्ठित करेगा ।

(3) यदि शिकायतकर्ता, अपनी शिकायत के संबंध में विनिश्चय में संतुष्ट नहीं है या यदि वह, यथास्थिति, अपनी शिकायत के प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, मार्गी गई प्रतिरोध प्राप्त नहीं करता है, तो वह अनुरोध कर सकता है कि उसकी शिकायत को अपने विवेक अधिकारी को और उसके बाद, यथास्थिति, मान्यावेदिक या केंद्रीय सरकार को अधेष्ठित किया जाए और ऐसे सब अनुपालन किया जाएगा । शिकायतकर्ता के लिए यह व्यायोक्तिहोगा कि वह उम दशा में सीधे अपने विवेक अधिकारी के पास गतीय करे, यदि वह अपनी शिकायत के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्याय उत्तर प्राप्त नहीं करता है ।

अध्याय 2

जांच बोर्ड

जांच बोर्ड का संयोजन

जब कभी कोई ऐसा मामला उत्पन्न हो जिस पर महानिदेशक या क्षेत्रीय मूल्यालयों के कमांडरों की पूर्ण रूप से जानकारी अपेक्षित हो, उसका अधिकारी द्वारा एक जांच बोर्ड संयोजित किया जा सकता ।

जांच बोर्ड का गठन

जांच बोर्ड में पीठासीन अधिकारी के रूप में एक अधिकारी और कम से कम दो ऐसे सदस्य होंगे जो या तो अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी होंगे या दोनों होंगे ऐसे अधिकारी या अधिनियम के अधीन नहीं हैं, सदस्य के रूप में उस समय नियुक्त किए जा सकेंगे जब बोर्ड जो किसी विशिष्ट प्रगति के मामलों का अध्ययन करना है और अन्तिम अधीनियम के अधीन प्रहोड़ वाले अधिकारी उपलब्ध न हों ।

जांच बोर्ड के कर्तव्य

(1) बोर्ड ऐसे कर्तव्यों का गठन करेगा जो बोर्ड संयोजित करने वाले प्राधिकारी द्वारा निविष्ट किए जाएं ।

(2) ऐसे निदेश सदस्य लिखित रूप में होंगे और अत्यावश्यकता के मामले में सकेत द्वारा पहुँचाए जा सकेंगे । विन्तु, बोर्ड संयोजित करने वाला अधिकारी उस फॉरमेट में होगा जो उपाधि में दिया गया है ।

39. जांच बोर्ड के लिए प्रक्रिया

(1) बोर्ड इन नियमों के उपर्युक्त और तहसमय प्रबृत्त तटरक्षक आवेदनों और संघीयक प्राविकारी के निवित्त श्रनुदेशों द्वारा भी मार्गीकृत होगा, परन्तु यह नव जब कि तटरक्षक आवेदन और निवित्त श्रनुदेश इन नियमों के उपर्युक्त से असंगत न हों।

(2) जांच बोर्ड को कार्यवाहियों जैसा के लिए खुली हड्डी नहीं होपी। केवल ऐसे व्यक्ति कार्यवाहियों में उपस्थित हो यहके जिन्हें बोर्ड द्वारा ऐसा करने के लिए अनुमति किया गया है।

(3) बोर्ड द्वारा यांत्रिक लिए गया प्रत्येक याकौशि हो नियमनिवित्त लाइनों में, जो धार्यवृत्त में लेखदात किए जाएँगे, युक्ति किया जाएगा: “आग निवारण एमें प्रत्येक का लेटर द्वारा से इंकार कर सकते हैं, जिसके उत्तर की प्रवृत्ति आपको किसी आस्ति या समयावधि की गांठका में डान नहीं है। इन संबंध में आर्टिल करना आप पर निर्भर करेगा और इसका विनियन द्वारा बोर्ड पर निर्भर करेगा कि आपको प्रश्न का उत्तर देता है या नहीं।”

(4) यज जमी किसी जांच में तटरक्षक में रोका कर रहे व्यक्ति का सरित्त या क्षमति प्रभावित होती हो या उसका परिणाम किसी हानि या नुकसान के लिए दायित्व या उत्तराधिकार के लाभक के लाभ में हो या वह किसी नियमों या नियमित या स्वानीय आदेशों के उल्लंघन के लिए की आती है, ऐसे नियमों को जांच के छीनन शुरू से अन्त तक उपस्थित रहने के लिए और जो उन्हें करने वाला कोई ऐसा साध्य देने, जो वह देने की इच्छा करे, और फिरी ऐसे साक्षी की प्रतिवाहिया नहीं, जिसका साध्य उसकी राय में ऐसे प्रभावित करता है तथा आपकी प्रतिवाहिया में कोई साक्षी देने के लिए पूरा अनुसर दिया जाएगा। बोर्ड का गांठासी अधिकारी ऐसी कारवाही करेगा जो यह सुनिविष्ट करने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार प्रभावित और पहुंच अधिसूचित न किया गया कोई ऐसा व्यक्ति इन नियमों के अधिन अपने अधिकारियों के अधेश की स्वीकार करा दे और उन्हें पूर्णतः करना है।

(5) बोर्ड का कार्यवाहियों सम्बन्ध प्रबृत्त तटरक्षक लाइनों में अतिरिक्त नहीं नियमों और अधिकारी द्वारा दिए गए किसी अनुदेशों के अनुसार अधिनिवित की जाएगा। ऐसे कार्यवाहियों के कार्यवृत्त में दिए गए सब साध्य के लाभदात निर्दिष्ट होंगे तथा सभी प्रश्नों और उत्तरों की कार्यवृत्त में आवश्यकता एवं कह में संदर्भित किया जाएगा।

(6) बोर्ड का कार्यवाहियों या बोर्ड के गमदा किया गया कोई संख्यकृत लक्षण या दिया गया किस प्रश्न का उत्तर दिया गया व्यक्ति, वही संघ के नियंत्रण करने संबंधित विविधों के अधीन है, के विवर माध्यमें गांधी नहीं होगा, न ही वह कार्यवाहियों को लाभदात कोई राफ्ट किसी ऐसी अवधि, के विवर दिया जाएगा। परन्तु इन नियमों के कोई भी बात किस साक्षी की प्रतिवर्तीका के प्रयोग के लिए कार्यवाहियों का अधोग किए जाने के लिए नहीं कहा।

40. जांच बोर्ड एंगेजिन होगा

(1) कोई जांच बोर्ड,-

(क) तटरक्षक पार्टी, अलायनों या नायान का बोना, उत्कूलन या परिस्टटप्पत इत्यता,

(ख) दिस्पांत के फलक/स्थापन/नायान का किस आकिर की कार्यवाहियों द्वारा द्वारा दिया गया गारंजिक धर्ति,

(ग) ऐसी वर्गित पुस्तकों या प्राज्ञों, जिनमें सुरक्षा संग जंतरेलिय हो, जो जाना,

(घ) सरकारी सम्बलि या गंडार का नुकसान या हानि या लोक धर्त की हानि,

(इ) प्राइवेट चेतावनी या नियरिंग की एवं नुकसान, जिसमें बाबा केन्द्रीय सरकार या नटरक्षक के विषय कोई दावा किए जाने का नियरिंग हो,

जैसे महान के किए; मामां में अधोग करने के लिए नियरिंग किया जा दिया।

(2) जांच बोर्ड का कार्यवाहियों द्वारा जांच बोर्ड, कार्यवाहियों वार्ड के पठाए न अधिकारी द्वारा धार्यवृत्त प्रधिकारी के समझ प्रस्तुत की जाएगी। कार्यवाहियों के प्राप्त होने पर, संघीयक प्रधिकारी—

(1) ऐसी कार्यवाहियों को जो उन्होंने अधिकारियों के गोप्ता हैं और जो यह करना चाहे सज्जे।

(2) उन्हें उन पर अपनी दिलाए नहिं, उच्चतर प्राविकारी के समझ प्रस्तुत करेगा, यदि ऐसे प्राविकारी के अधीन ऐसा करना आवेदित हो।

(3) बोर्ड की कार्यवाहियों की प्रतिवित्ति नियमनिवित्त अधिकृत बोर्ड की कार्यवाहियों की एवं प्रति दिलाए करने के दृष्टिकोण—

(क) प्रधिनिवित के अधीन कोई ऐसा अधिकृत जिसका किसी ऐसे मामले या अन्त, जिसकी रिपोर्ट बोर्ड द्वारा की गई है, की विवर विचारण किसी नए अधिकृत न्यायालय द्वारा किया जाए है, या

(ख) जब तक कि महानिवितक किसी काण्डारण अन्यथा प्रदिला न देसरकारी सेवा में कोई ऐसा अधिकृत विवर की विवर, भावरण या अप्ति महानिवितक की राय में, बोर्ड के उत्तर महान में इच्छा वाले से प्राप्ति की होती है।

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोगन के लिए कार्यवाहियों के अधिगत बोर्ड के नियरिंग भी होंगे किन्तु इनके प्रयोग कोई किसी अधिकारियों नहीं होपी।

प्रधानम् 8

आवेदन और अर्जियां

43. किसी तटरक्षक न्यायालय के नियरिंग और विद्यारेत के विषय आवेदन और अर्जियां

(1) प्रधिनिवित के अधीन कोई एसा अधिकृत जिसका विचारण किसी तटरक्षक न्यायालय द्वारा किया गया, मुख्य विधि प्राविकारी को प्रधिनिवित की धारा 117 के प्रधीद तटरक्षक न्यायालय की कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) कोई अर्जी, अधिनिवित की धारा 119 में घोषित किसी प्राविकारी को दी, जाने के लिए, अनुमति होगी।

44. परिसंसामा की अधिकृत न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन उस तारीख से जिसकी तटरक्षक न्यायालय द्वारा दृष्टिकोण पर्याप्त किया गया था, 31 विन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 119 के अधीन कोई अर्जी तटरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण की कार्यवाहियों के संघर्ष में मुख्य विधि प्राविकारी द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन पर महानिवितक के आवेदन की तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी :

परन्तु ऐसे अधिकृत द्वारा कार्यवाहियों या मुख्य विधि प्राविकारी द्वारा कार्यवाहियों के संघर्ष में न्यायिक पुनर्विलोकन पर महानिवितक के आवेदनों की प्रतिवित्ति अधिग्राह्यता करने में दिए गए समय की अवास्थिति 21 विन या 3 मास की अवधि को संघर्षना करने में नहीं लिया जाएगा :

परन्तु यह और कि पूर्वावधि अधिकृत की समाप्ति के पश्चात प्राप्त कोई आवेदन, यास्त्रियति, महानिवितक या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस धर्त में प्रदृश किया जा सकेगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि विलम्ब ऐसे कारणों से हुआ है जो आवेदक के नियंत्रण के बाहर हैं।

45. आवेदन और अर्जी प्रस्तुत करने का ढंग

(1) कोई आवेदन या कोई अर्जी स्वयं प्रस्तुत की जा सकेगी या रजिस्ट्रीकृत गांडा द्वारा भेजी जा, सकेगी। या दो प्राप्तियों में होगी

और आवेदन द्वारा हस्ताक्षरित होगी। इसमें उन आधारों को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से कथित किया जाएगा जिन पर बोयलिंग या दण्डादेश के विरुद्ध आवेदन किया गया है। यदि आवेदन अधिनियम की धारा 117 के अधीन है, तो आवेदक को यह भी कथित करता चाहिए कि क्या वह स्वयं या किसी विधि अवश्यकी या तटरक्षक के किसी अधिकारी की भारपत्र सुने जाने की इच्छा करता है। यदि अर्जी अधिनियम की धारा 119 के अधीन है, तो वैयक्तिक मुनाफाई करता अपेक्षित नहीं है।

(2) धारा 117 के अधीन आवेदन सीधे मुक्त विधि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 119 के अधीन अर्जी, उस कमांडर तटरक्षक को, जिसने समावेश में विचारण हुआ था, की मार्फत प्रस्तुत की जाएगी। कमांडर तटरक्षक को, उसे प्रत्यनी ठिकानियों सहित एक मास के अवधि के भौतिक महानियों को अपेक्षित करेगा।

अधिकारी :

स्थान :

तारीख :

प्रेषिती :

जांच बोर्ड के लिए आवेदन

आपसे, जांच बोर्ड के रूप में, जिनका पोठानीन अधिकारी —————— द्वारा, —————— में —————— 198 को बजे समयत होने और —————— की परिस्थितियों का पूर्णका और सावधानो से अनेक फरते के लिए अनुरोध किया जाता है।

2. आपके रिपोर्ट के साथ मीडिक रूप से लिए गए साक्ष्य के कार्यद्रूत होंगे और उसमें साक्ष्य द्वारा प्रकट किए गए मामले के गुणवत्ता पर आपकी राय की अधिकता होगी; उसमें यह भी पूर्णतः कथित होगा कि किसका, क्या किसी घटित का, और किस सोमात तक, वोर माना जा सकता है।

3. कार्यपाल में प्रश्न को आधोंसात एक ऋतु में संबोधित किया जाएगा, और कार्यद्रूत साथ रिपोर्ट पर बोर्ड के पोठानीन अधिकारी और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। परोक्षाधीन साक्षी का नाम, वो जाने वालों रिपोर्ट और कार्यद्रूत के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर नोट किया जाएगा।

4. कार्यद्रूत और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले, आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि बोर्ड की कार्यवाहियों में निविष्ट एवं कागजपत्र के साथ मूल (या यदि मूल उपलब्ध नहीं है तो उनकी प्रतिलिपियों) और कार्यद्रूत की सभी प्रतिलिपियाँ हैं, तथा कार्यद्रूत को फिरारे और उन्हें प्रस्तुत करने से विविध मियाओं का पूर्णतया बालन किया गया है।

5. कोई ऐसा अन्य मामला, जो कार्यवाहियों से उत्पन्न होता है और जिस पर बोर्ड विवार करता है, संयोजक अधिकारी की जानकारी में लाया जाएगा और वह पूर्व के रिपोर्ट का विषय होगा।

6. आप तटरक्षक (साधारण) नियम, 1986 के अध्याय 7 के उपर्योग द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

7. —————— द्वारा प्रत्येक दौरान आवाहित करने की आवश्यकता नहीं है, के हाजिर किए जाने को अवश्या करेगा।

8. ——————, किसी गोपनीय जांच के दौरान आवाहित की ओर आवरक लेखन-सामग्री को अवश्या करेगा।

9. सभी सुरक्षा कागजपत्र, बोर्ड के पोठानीन अधिकारी को इसके साथ सौंपे जाते हैं जो उन्हें सभग्रन्थ में कार्यद्रूत के साथ लीटा देगा।

(संयोजक अधिकारी के हस्ताक्षर)

MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 1986

S.R.O. 4 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a), (d), (e), (f), (k) and (l) of sub-section (2) of section 123 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978), the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Coast Guard (General) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

(3) संक्षिप्ततः इष्ट देने के विरुद्ध अर्जी ग्रहण नहीं की जाएगी। यदि ऐसी आवाहित परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण निष्कर्ष या संक्षिप्ततः दिए गए दण्डादेश में हस्ताक्षर करना आवश्यक है तो मामले को उचित प्रणाली के माध्यम से उठायक मुख्यालय को, ऐसे पूर्ण अधीन सहित, जिनमें यथास्थिति, महानियों या केन्द्रीय मामलों का पूर्ण अधिकारी का प्रयोग आवश्यक हो, अन्वेषित किया जाए। अधिनियम की धारा 119 के अधीन किसी अर्जी की दशा में, परिस्थिति की अवधि उस तारीख से जिसका संक्षिप्त दण्ड दिया गया था, तीन मास से अधीन।

[फा. सं. एन. एन. 10216]
टी. नो. बैठार्जी, संयुक्त सरिय
रक्षा मंत्रालय अ० त्रिं. सं० एन० इन० इन० 0216/746/इ (नेव०-3) / 86,
तिंकू 3-5-1986
स्पष्टवन्धु

(नियम 38)

2. Definitions. In these Rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978) ;
- (b) "Annexure" means Annexure appended to these Rules ;
- (c) "Board" means the Board of Inquiry convened under Rule 36 ;
- (d) "Coast Guard Order" means the order issued by the Director General of the Coast Guard ;
- (e) "Coast Guard Region" means a Coast Guard Region specified in sub-rule (3) of Rule 4 ;
- (f) "Executive Officer" means an officer who carries out executive duties of the ship ;
- (g) "Regional Commander" means the Commander, Coast Guard Region specified in sub-rule (2) of Rule 4 ;
- (h) Words and expressions used but not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Reports and Application.—Any report or application directed by these rules to be made to a Coast Guard authority, shall be made in writing through the proper channel, unless the said authority on account of exigencies of service or otherwise dispenses with the writing.

CHAPTER II

ORGANISATION

4. Constitution of the Coast Guard.—(1) The Coast Guard shall consist of officers, subordinate officers, sailors and other enrolled persons, appointed to, or enrolled into, the Coast Guard Service.

(2) The Director General shall exercise command through the following authorities :—

- (a) The Commander, Coast Guard Region, West ;
- (b) The Commander, Coast Guard Region, East ;
- (c) The Commander, Coast Guard Region, Andaman and Nicobar Islands ; and
- (d) The Commander, Coast Guard Customs.

(3) (a) The Coast Guard Region, West, shall comprise of the Coastal areas and the maritime zones of India along the coastal areas of the States of Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala and the Union Territories of Goa, Daman and Diu and Lakshadweep ;

(b) The Coast Guard Region, East, shall comprise of the coastal areas and the maritime zones of India along the coastal areas of the States of Tamil

Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, West Bengal and the Union Territory of Pondicherry ;

(c) The Coast Guard Region, Andaman and Nicobar Islands, shall comprise of coastal areas and the maritime zones along the coastal areas of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

(d) The Commander, Coast Guard Customs, shall exercise operational and administrative control on all ships assigned to him by the Director General.

5.—Each Coast Guard Region shall be further divided into districts and each district shall be under the supervision of the District Commander to be appointed by the Director General.

6.—The Director General shall establish such number of stations and shall assign such number of ships to each Coast Guard Region|district|station as he may think fit depending upon the exigencies of the service from time to time.

CHAPTER III

RANK AND COMMAND

7. Classifications and Ranks.—The officers and other members of the Coast Guard shall be classified in accordance with their ranks in the following categories, namely :—

- (a) Officers.—
 - (i) Director General ;
 - (ii) Inspector General ;
 - (iii) Deputy Inspector General ;
 - (iv) Commandant ;
 - (v) Deputy Commandant ;
 - (vi) Assistant Commandant.
- (b) Subordinate Officers—
 - (i) Pradhan Adhikari|Pradhan Sahayak Engineer ;
 - (ii) Uttam Adhikari|Uttam Sahayak Engineer ;
 - (iii) Adhikari|Sahayak Engineer.

- (c) Sailors—
 - (i) Pradhan Navik|Pradhan Yantri ;
 - (ii) Uttam Navik|Uttam Yantri ;
 - (iii) Navik|Yantri.

8. Branches.—(1) The branches into which officers are classified shall be, —

- (a) General Duties ;
- (b) Technical.

(2) The branches into which enrolled persons are classified shall be, —

- (a) General Duties ;
- (b) Technical ;
- (c) Domestic ;
- (d) Enrolled followers.

9. Specialisations.—The officers and enrolled persons shall be eligible for specialisation as follows, namely :—

Categories of personnel	Specialisation	Sub-Specialisation
1	2	3
(a)(i) Officers (General Duties)	Pilot Navigator. Law. Pollution Control. Salvage. Diving.	Not applicable
(ii) Officers (Technical)	Aviation Engineering. Electrical Engineering. Electronic Engineering, Pollution Control. Salvage. Naval Architecture. Marine Engineering.	Not applicable
(b)(i) Subordinate officers and sailors (General Duties)	Seaman.	Gunners Mats. Quarter Master. Radio Operator. Airman. Diver. Engineering. Air Engineering. Electrical. Air Electrical. Air Radio.
(ii) Subordinate officers and sailors (Tech- nical)	Marine Engineering. Air Engineering. Electrical Engineering. Air Electrical Engineering. Electronic Engineering. Air Electronic Engineering. Hull Engineering.	Not applicable.
(iii) Subordinate officers and sailors (Domestic)	Supply Assistants. Cooks. Stewards.	Not applicable.

10. Command of Coast Guard Ships.—(1) Command of Coast Guard Ships, vessels, aircrafts or such establishments as may be promulgated by the Director General will be considered as operational command.

(2) Generally officers and enrolled persons of the General Duties Branch shall exercise operational command, or direct any work or undertaking which requires the co-operation of different branches of the Coast Guard Service. It may be conferred on other officers and enrolled persons by appointment or by direction by the Director General.

(3) Command of ships|vessels|aircrafts shall be limited to qualified officers of the General Duties branch and enrolled persons of seaman specialisation, except when conferred by superior authority on other persons qualified by ability and experience.

(4) Command of Coast Guard ships|vessels, establishments and aircrafts may also be exercised by the officers and sailors of the Indian Navy while on deputation to the Coast Guard, when specifically appointed by the Director General.

(5) Technical Officers appointed in command of shore establishments may exercise such functions of command as may be necessary for the proper performance of their duties.

(6) Officers holding appointments under civil departments of the Government shall not, without the

express orders of the Director General, assume any command over, or issue any orders to, the personnel of the Coast Guard, other than to those officers and enrolled persons who are serving under them in their respective departments.

11. Officer in Command—Rank and precedence—Officers in command of Coast Guard ships shall take rank and precedence over the officers placed under their command on all occasions, whether on shore or afloat.

12. Command in Temporary Absence of Commanding Officer.—Except in a shore establishment, the senior general duties officer on board (other than an officer appointed additional for staff or special duties, or an officer not qualified to command ships|vessels) shall, in the temporary absence of the Commanding Officer, assume the powers and duties of the Commanding Officer. In a shore establishment, command shall descend in the branch of the Commanding Officer. If no officer of the Commanding Officer's branch is present, then command shall devolve on the seniormost officer present ; but command shall not devolve on any officer appointed additional for staff or special duties or for courses.

13. Authority of officer of the Watch.—Every officer below the rank of the Deputy Inspector General (not being either the Executive Officer or the Commanding Officer of the ship for the time being) and

enrolled person shall be subordinate to the officer of the watch, whatever may be his rank, in regard to the performance of the duties with which he is charged.

14. How Officers and Enrolled persons are to be borne.—(1) Officers and enrolled persons serving afloat or ashore shall be borne on the books of the ship or establishment or station in which they are serving or to which they are attached.

(2) When it is desired that an officer borne additional for staff or special duties should practice or gain experience in ship handling and the like, authority for him to take charge of a watch at sea or in harbour may be given by the Commanding Officer :

Provided that nothing in this rule shall put him in the line of succession to command.

15. Officer promoted.—An officer, who is promoted shall continue to perform the duties he has been assigned, and shall take rank and command of the new rank only if he is reappointed to his ship in the higher rank.

16. Officers on Deputation.—Officers deputed by the competent authority to do duty on board any other ship, although borne as supernumeraries, shall take the same rank and command, and be considered in every respect for the time they are so employed, as if they actually belonged to the complement.

17. Officers taking passage.—Any officer taking passage in one of the Coast Guard ships, may, though borne as supernumerary, be ordered to do duty if inferior or junior in rank to the Executive Officer of the ship in which he is embarked. While so employed he shall take the same rank and command, and shall be considered in every respect as if he actually belonged to the complement. In the event of the death of the Commanding Officer of the ship, the acting command thereof shall vest in the officers mentioned in rule 12 and in no case shall be assumed by a supernumerary officer except on the express authority from the Director General.

18. Authority of Army, Navy and Air Force Officers.—An officer of the Army, Navy and Air Force

appointed to the Coast Guard shall have and exercise all such powers as are vested in or may be exercised by an officer of the Coast Guard of the corresponding rank or holding a corresponding appointment.

19. Subject to the provisions of sections 57 and 58 of the Act, when a person subject to the Act is attached to any body, or serving in a unit, or admitted as a patient in a hospital of the regular Army, Navy or Air Force, the Commanding Officer of such body, unit or hospital shall exercise all powers of Command over officers junior to him in rank and all powers of command and punishment over enrolled personnel.

CHAPTER IV

RETIREMENT, DISMISSAL, REMOVAL, DISCHARGE OR RELEASE

20. Retirement.—(1) Retirement age for officers holding a rank higher than that of a Commandant shall be fifty-eight years and for officers of other ranks it shall be fifty-five years.

Provided that the Central Government may extend the retirement age of :—

- (a) An officer of the rank higher than that of a Commandant for a period of one year at a time but not, in any case, beyond the age of sixty years ;
- (b) Officers of other ranks for a period of one year at a time but not, in any case, beyond the age of fifty eight years.

(2) Retirement age of subordinate officers and sailors shall be fifty five years.

21. Dismissal, removal, discharge or release.—(1) Authorities specified in column 1 shall be competent to authorise dismissal, removal, discharge or release of the members of the Coast Guard specified in column 2, on the grounds stated in the corresponding entries in column 3, in accordance with the procedure specified in column 4 of the Table annexed hereto. Any power conferred by this rule on any of the aforesaid authorities may also be exercised by any other authority superior to it.

TABLE

Competent Authority 1	Member of the Coast Guard 2	Grounds on which service can be terminated 3	Procedure for termination of service 4
Central Government	Officers	(i) Misconduct	As per procedure prescribed under Rule 22.
		(ii) Unsuitability	As per procedure prescribed under Rule 22.
		(iii) Unsatisfactory progress in training	As per procedure prescribed under Rule 24.
		(iv) Furnishing False/wrong information at the time of recruitment.	As per procedure prescribed under Rule 25.
		(v) Unfitness on medical grounds	As per procedure prescribed under Rule 26.

1	2	3	4
Inspector General	Subordinate officers and sailors	(vi) On own request (i) Misconduct (ii) Unsuitability (iii) Unsatisfactory progress during training (iv) Furnishing false/wrong information at the time of recruitment (v) Unfitness on medical grounds (vi) On own request	As per procedure prescribed under Rule 27. As per procedure prescribed under Rule 23. As per procedure prescribed Under Rule 23. As per procedure prescribed under Rule 24. As per procedure prescribed under Rule 25. As per procedure prescribed under Rule 26. As per procedure prescribed under Rule 27.

22. Procedure for dismissal/removal of officers.—(1) When it is proposed to dismiss/remove an officer under section 11, he shall be given an opportunity to show cause in the manner specified in sub-rule (2) :

Provided that this sub-rule shall not apply —

- (a) Where the officer is dismissed/removed from the service on the grounds of misconduct which has led to his conviction by the criminal court.
- (b) Where the Central Government is satisfied that, for reasons to be recorded, it is not expedient or reasonably practicable to give the officer an opportunity of showing cause.

(2) When after considering the reports of the officer's misconduct, the Director General is satisfied that the trial of the officer by a Coast Guard Court is not expedient or not practicable and is of the opinion that the further retention of the officer in the service is not desirable, the Director General shall so inform the officer together with all the reports adverse to him, and he shall be called upon to submit in writing his explanation and defence :

Provided that the Director General may, with the prior approval of the Central Government, withhold from disclosure any such reports, or portion thereof, if its disclosure is not in the interest of the security of the State.

(3) In the event of the explanation of the officer being considered unsatisfactory by the Director General, or when so directed by the Central Government, the case shall be submitted to the Government with the officer's defence and the recommendations of the Director General as to the termination of officer's service in the manner specified in sub-rule (5).

(4) Where, upon the conviction of an officer by a criminal court, the Central Government or the Director General considers that the conduct of the officer which has led to his conviction renders his further retention in the service undesirable, a certified copy of the judgement of the criminal court convicting him shall be submitted to the Central Government with the recommendations of the Director General as to termination of the officer's service in the manner specified in sub-rule (5).

(5) When submitting a case to the Central Government under sub-rule (3) or (4), the Director General shall make his recommendation whether the officer's service should be terminated and if so, whether the officer should be

- (a) dismissed from the service ; or
- (b) removed from the service.

(6) The Central Government, after considering the reports and the officer's defence, if any, or the judgement of the criminal court, as the case may be, and the recommendation of the Director General, may dismiss or remove the officer from the service.

(7) When the Director General is satisfied that an officer is unfit to be retained in the service on the grounds of unsuitability, he may, after giving the officer an opportunity to explain his case, recommend to the Central Government that the officer's service be terminated. The Director General shall also forward to the Central Government the reasons for his recommendations and the record of service of the officer :

Provided that where in the interest of security of the State it would be inexpedient to give the officer an opportunity to explain his case, it shall be lawful for the Central Government to pass an order terminating the service of the officer without giving the officer an opportunity to explain his case.

(8) The Central Government on receipt of the report under sub-rule (7) may pass an order as it may deem fit for the dismissal or removal of the officer.

(9) The Central Government may in suitable cases retire or remove the officer with or without pension or gratuity.

23. Procedure for dismissal/removal of enrolled persons.—(1) Where the Commanding Officer is satisfied that an enrolled person is considered unsuitable to be retained in the service on the grounds of misconduct or unsuitability, he may make a recommendation to the Inspector General in the Coast Guard Headquarters for the dismissal/removal of such person from the Coast Guard.

(2) In all cases of recommendation for dismissal|removal of a person, the Commanding Officer shall establish clearly the fact that the person has been given a suitable warning and sufficient time to improve. Documentary evidence to this effect shall accompany the recommendation.

(3) Where, upon the conviction of an enrolled person by a criminal court, the Deputy Inspector General under whom the person is serving considers that the conduct of the person which has led to his conviction renders his further retention in the service undesirable, a certified copy of the judgement of the criminal court convicting him shall be submitted to the Inspector General in the Coast Guard Headquarters with the recommendations of the Deputy Inspector General under whom the person is serving as to the termination of the person's service in the manner specified in sub-rule (4).

(4) The Inspector General in the Coast Guard Headquarters on receipt of a recommendation under sub-rule (1) or (3) may pass an order dismissing or removing the person concerned from the service.

(5) The Inspector General in the Coast Guard Headquarters may in suitable cases retire or remove the person with or without pension on gratuity.

24. Procedure for discharge|release on grounds of unsatisfactory progress in training.—(1) When it is proposed to discharge|release a member of the Coast Guard from the service on account of unsatisfactory progress in training, the Commanding Officer of training establishment, where the person is undergoing training, shall make a recommendation to the Central Government, or the Inspector General in the Coast Guard Headquarters as the case may be for the discharge or release of the person.

(2) In all cases of recommendations for discharge or release of a person, the Commanding Officer of the training establishment shall establish clearly the fact that the person has been given suitable warning and sufficient time to show progress, documentary evidence to this effect shall accompany the recommendation.

(3) The Central Government or as the case may be the Inspector General in the Coast Guard Headquarters on receipt of recommendation under sub-rule (1), may discharge or release the person concerned from the service.

25. Procedure for discharge|release on grounds of furnishing false|incorrect information at the time of recruitment.—The Central Government, or as the case may be, the Inspector General in the Coast Guard Headquarters may discharge or release a person subject to the Act on grounds of furnishing false|wrong information at the time of the recruitment of that person in the service. A show cause notice shall be issued to the individual before the person is discharged|released from the service.

26. Retirement|release|discharge on grounds of physical unfitness.—(1) When a person subject to the Act is found to be permanently unfit for the Coast Guard service by a Medical Board constituted under the Regulations for the Medical Services of the Armed Forces, he may be retired, released, or discharged from the service in accordance with the procedure laid down in this rule.

(2) The President of the Medical Board, shall immediately after the Medical Board has come to the conclusion that the person is permanently unfit for any form of Coast Guard service, issue a notice specifying the nature of the disease or disability he is suffering from and the finding of the Medical Board and also inform him that in view of the finding he may be retired, released or discharged from the service :

Provided that where in the opinion of the Medical Board the person is suffering from a mental disease and it is unsafe to communicate the nature of the disease or disability to the person, or the person is unfit to look after his interest, the nature of the disease or disability shall be communicated to the person's next of kin who shall have the right to petition under sub-rule (3).

(3) Such notice shall also specify that the person may within fifteen days of the date of receipt of the notice prefer a petition against the findings of the Medical Board to the President of the Medical Board.

(4) If no petition is preferred within the time specified in sub-rule (3), the person may be retired, released or discharged from the service, by an order to that effect made by the Central Government, in the case of officers, and by the Inspector General in the Coast Guard Headquarters in the case of enrolled persons.

(5) If a petition is preferred within the time specified in sub-rule (3), the President, Medical Board shall refer it to an Appeal Medical Board, constituted under the Regulations for the Medical Services of the Armed Forces, for its decision on the petition. The findings of the Medical Board together with the records concerning the case shall be forwarded to the Director General in the Coast Guard Headquarters. In case there is no difference in the findings of the two Medical Boards, the person may be retired, released or discharged from the service, by an order to that effect made by the Central Government, in the case of officers, and by the Inspector General in the Coast Guard Headquarters in the case of enrolled persons.

(6) In the case of a difference in the findings of the Medical Board and the Appeal Medical Board, the Director General in the case of officers, or the Inspector General in the Coast Guard Headquarters in the case of enrolled persons, shall refer the matter to a Review Medical Board, constituted for the purpose under the Regulation for the Medical Services of the Armed Forces, for an opinion before retiring, releasing or discharging a person from the service on the ground of physical unfitness.

27. Procedure for discharge|release or retirement on own request.—(1) A member of the Coast Guard may, in exceptional cases, obtain his discharge, release or retirement from the service on extreme compassionate grounds, i.e. in cases where it is clear that undoubtedly material hardship will be caused to the member of the Coast Guard or his family members by his retention in the service.

(2) The Central Government may, having regard to the circumstances of any case, permit discharge, release or retirement of an officer from the service before attaining the age of retirement. The question

of discharge, release or retirement shall be a matter within the discretion of the Central Government.

(3) The Inspector General in the Coast Guard Headquarters may discharge, release or retire a member of the Coast Guard other than an officer on compassionate grounds.

(4) Application for discharge, release or retirement on compassionate grounds shall be forwarded by the Commanding Officer to the Inspector General in the Coast Guard Headquarters through the Regional Commander.

28. Date from which retirement|dismissal|removal takes effect.—(1) The date of removal, resignation or discharge of a person subject to the Act shall take effect

from the date specified in that behalf in the order of retirement, dismissal, removal, resignation or discharge as the case may be.

(2) Retirement, dismissal, removal, resignation or discharge of a person subject to the Act shall not be retrospective.

CHAPTER V

PRESCRIBED OFFICERS AND AUTHORITIES

29. Prescribed Officers and Authorities.—The officers and authorities mentioned in columns (3) and (4) of the Table below, shall be the prescribed officers and prescribed authorities under sections mentioned in column (1) for the purposes mentioned in column (2) of the said Table.

Section of the Act	Purpose	Prescribed officer	Prescribed authority
1	2	3	4
Section 8	To administer oath or affirmation.	Any officer	—
Section 9	For resignation and withdrawal from the post.	—	1. The Central Govt. for officers. 2. The Inspector General in the Coast Guard HQs for enrolled person.
Section 13(1)	For granting previous sanction to form association, etc., under clauses(a), (b) and (c) and of sub-section (1)	—	1. The Director General for officers. 2. The Inspector General in Coast Guard HQs for enrolled persons.
Section 63(1)	Appointment of Coast Guard Police officers.	Commanders, Regional Headquarters.	—
Section 71	To decide the choice of criminal court or Coast Guard Court for initiation of proceedings under the Act.	The Commanding officers under whose command the accused is serving.	—
Section 86(1)	To sign letters, returns or other documents.	The Director (Personnel) Coast Guard Headquarters and officer-in-Charge, Bureau of Naviks.	—
Section 89	1. For taking steps for trial of a person of unsound mind. 2. Certificate of fitness to attend trial.	The officers who ordered original trial by the Coast Guard court.	Medical Officer of the lunatic asylum or other place of safe custody where the person is kept.
Section 97	To order interim custody of a person sentenced to death.	The Commanding officer under whose command the accused person was serving.	—
Section 98	To give directions for execution of sentence to death.	The Commanding Officer under whose command the accused was serving.	—
Section 100 (1)	To give directions for confinement in a Civil prison.	The officer who ordered trial by the Coast Guard Court.	—
Section 100 (2)	To issue warrant for confinement of a person to a Civil prison.	The Executive Officer of the person under sentence.	—
Section 103	To issue warrant containing an order setting or varying any sentence to the officer in charge of a civil prison.	The Commanding Officer of the person under sentence.	—

30. For the purpose of section 57, the authorities mentioned in column (1) and holding ranks mentioned in column (2) shall have the power to award

punishment to the extent mentioned in column (3) of the Table below :

TABLE

Authority (1)	Ranks (2)	Extent to which punishment could be awarded. (3)
1. The Commanding officer	All ranks	All punishments.
2. Executive Officer	(1) Commandant (2) Deputy Commandant (3) Assistant Commandant	(i) Mallet of pay and allowances for first offence of leave breaking upto 48 hours to all enrolled persons. (ii) Extra work and drill for a period not exceeding 14 days to Naviks. (iii) Stoppage of leave for a period not exceeding 30 days to all enrolled persons. (iv) Admonition to all enrolled persons. (i) Mallet of pay and allowances for the first offence of leave breaking upto 36 hours to all enrolled persons. (ii) Extra work and drill for a period not exceeding 7 days to Naviks. (iii) Stoppage of leave for a period not exceeding 15 days to all enrolled persons. (iv) Admonition to all enrolled persons. (i) Extra work and drill for a period not exceeding 7 days to Naviks. (ii) Stoppage of leave for a period not exceeding 15 days to other than subordinate officers. (iii) Admonition to persons other than subordinate officers. (i) Extra work and drill for 1 day to Naviks. (ii) Admonition to Naviks.
3. Officers of the Watch/Officer of the Day.	Assistant Commandant and above.	

31. Oath or affirmation.—Every member of the Coast Guard shall make and subscribe an oath or affirmation in the following form :—

FORM OF OATH/AFFIRMATION

I, A.B. do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will as in duty bound, honestly and faithfully serve with Coast Guard wherever ordered, by air, land or sea and that I will observe all commands of the President of the Union of India and Commands of any officer set over me even to the peril of my life.

Signature—_____

Counter-signature—_____
(Name and designation of person administering oath).

CHAPTER VI

COMPLAINTS AND REPRESENTATIONS

32. Complaints to higher authorities.—(1) If an officer or an enrolled person thinks that he has suffered any personal oppression, injustice, or other ill treatment or that he has been treated unjustly in any way or wishes to make a representation affecting

his welfare or has any suggestion to make in connection with service, he shall bring it to the notice of his superior officer.

(2) It shall be the duty of the superior officer to whom a representation has been given, to forward the same to the higher authorities for appropriate action.

(3) Any other method of seeking redressal from the superior officer/authority save those mentioned in these rules is forbidden.

33. To whom complaint shall be made.—(1) If the complainant is a Commanding Officer of the Coast Guard Ship, his complaint shall be in writing and shall be addressed to his immediate superior officer.

(2) If the complainant is an officer serving in one of the Coast Guard Ships his complaint shall be made orally to the Commanding Officer whereby a complainant is to make an oral request to see the Commanding Officer for that purpose. If the complainant is an officer, such request shall be made through the Executive Officer and if the complainant is a head of the department, a request shall be made direct to the Commanding Officer. If the complainant is an officer working in a particular department, the request shall be made in the first place to the head of the department.

(3) If the complainant is an enrolled person, his complaint shall be made orally to the Commanding Officer. A request to see the Commanding Officer shall be made to the Executive Officer through the complainant's Divisional or Departmental Officer. An enrolled person detached from his ship or his establishment shall make his complaint to the officer in whose command he may be at that time.

34. Rules to be observed by the complainant.—(1) The complaint shall be confined to statement of facts on which the complaint is based and to the alleged consequences to the complainant himself.

(2) Joint complaints by two or more persons are not allowed. Each individual shall make his own complaint.

(3) It shall be the duty of the person making a complaint, either oral or written, to ensure that,—

- (a) the statement of facts in the complaint is true to the best of his knowledge; and
- (b) the complaint is not made in a language which is disrespectful, insubordinate or subversive to discipline.

35. How the complaint shall be dealt with.—(1) On receipt of any complaint the Commanding Officer, or other officer, receiving the same shall satisfy himself that the complaint is made in accordance with these rules. He shall then deal with it in the exercise of his discretion as may seem to him right and cause the complainant to be informed of his decision.

(2) If the Commanding Officer or the other officer receiving complaint refuses or is unable to remedy the complaint so made, the complainant may respectfully ask that he may be allowed to make his complaint in writing. On receiving such request, the Commanding Officer, or the other officer, shall give the complainant 24 hours to reconsider the matter. The complainant may then address his complaint in writing to the Commanding Officer, or the other officer, who shall then forward the complaint to the next superior officer together with his remarks thereon.

(3) If the complainant is not satisfied with the decision on his complaint or if he does not get the redress asked for within a period of one month from the date of submission of his complaint or the date of its despatch to the next superior authority, as the case may be, he may request that his complaint be forwarded to the next superior authority and so on to the Director General or the Central Government, as the case may be, and all such requests shall be complied with. The complaint shall be justified in appealing direct to the next superior authority if he does not receive a final reply within a period of six months from the date of submission of his complaint.

CHAPTER VII

BOARD OF INQUIRY

36. Convening of Board of Inquiry.—A Board of Inquiry may be convened by the Director General or by Commanders of Regional Headquarters whenever any matter arises upon which the said authority requires to be thoroughly informed.

37. Constitution of Board of Inquiry.—A Board shall consist of an officer as Presiding Officer and at least two members who shall be either officers or subordinate officers or both. Persons not subject to the Act may be also appointed as member when the Board is to investigate matters of a specialised nature and officers subject to the Act with the requisite qualifications are not available.

38. Duties of the Board.—(1) Board shall perform such duties as may be directed by the authority convening the Board.

(2) Such directions shall always be made in writing and may in case of urgency be conveyed by signal. However, the order convening the Board shall be made in the format given in the Annexure.

39. Procedure for Board of Inquiry.—(1) The Board shall be guided by the provisions of these rules and also by the Coast Guard Orders, for the time being in force, and the written instructions of the convening authority; provided that the Coast Guard Orders and the written instructions are not inconsistent with the provisions of these rules.

(2) The proceedings of the Board of Inquiry shall not be open to the public. Only such persons may attend the proceedings as are permitted by the Board to do so.

(3) Every witness examined by the Board shall be informed in the following terms which shall be recorded in the minutes :—

“You are privileged to refuse to answer any question, the answer to which may tend to expose you to any penalty or forfeiture. It will be for you to raise the objection and for the Board to decide whether you must answer the question or not.”

(4) Whenever an enquiry affects the character or reputation of a person serving in the Coast Guard or may result in the imputation of liability or responsibility for any loss or damage, or is made for the contravention of any rules or general or local orders, full opportunity shall be afforded to such person for being present throughout the enquiry and of making any statement and of giving any evidence he may wish to make or give, and of cross-examining any witness whose evidence in his opinion affects him, and producing any witness in his defence. The Presiding Officer of the Board shall take such steps as may be necessary to ensure that any such person so affected and not previously notified receives notice of, and fully understands, his rights under these rules.

(5) The proceedings of the Board shall be recorded in accordance with any directions contained in the Coast Guard Orders for the time being in force and any instructions given by the convening authority. The minutes of such proceedings shall contain a verbatim report of all the evidence given, and all questions and answers shall be numbered in one series throughout the minutes.

(6) The proceedings of the Board or any confession, statement, or answer to a question made or given before the Board, shall not be admissible in

evidence against a person subject to the laws relating to any Armed Forces of the Union nor shall any evidence respecting the proceedings of the Board be given against any such person. Provided that nothing in these rules shall prevent proceedings from being used for the purpose of cross-examining any witness.

40. Board of Inquiry when to be held.—(1) A Board of Inquiry may be convened to investigate into any matter of importance such as,—

- (a) loss, stranding or hazarding of Coast Guard Ships, Vessels, or Air Craft ;
- (b) accidental death of, or serious bodily injury to, any person on board a ship|Establishment|Air Craft ;
- (c) loss of classified books or publication involving breach of security ;
- (d) damage to or loss of Government property or stores, or loss of public money ;
- (e) damage to private persons or property, in respect of which there is likely to be a claim against the Central Government or the Coast Guard.

41. Action on the proceedings of Board of Inquiry.—The proceedings of the Board of Inquiry shall be submitted by the Presiding Officer of the Board to the convening authority. On receipt of the proceedings the convening authority shall—

- (i) take such action as is within its jurisdiction and as it may deem fit to take ;
- (ii) submit the same together with its comments thereon to the higher authority, if required to do so under the orders of such authority.

42. Copies of the proceedings of the Board.—The following persons shall be entitled to receive a copy of the proceedings of the Board :—

- (a) Any person subject to the Act who is tried by a Coast Guard Court in respect of any matter or thing which has been reported by the Board ; or
- (b) Any person in Government service whose character, conduct or reputation is, in the opinion of the Director General, affected by anything in the evidence before the Board, unless the Director General sees reason to order otherwise.

Explanation : For the purpose of these rules proceedings shall include findings of the Board but shall not include recommendations of the Board.

CHAPTER VIII

APPLICATIONS AND PETITIONS

43. Application and Petitions against findings and sentence of a Coast Guard Court.—(1) A person subject to the Act, who has been tried by a Coast Guard Court, may make an application to the Chief

Law Officer for review of the proceedings of the Coast Guard Court under section 117 of the Act.

(2) A petition shall also be allowed to be made to any authority mentioned in section 119 of the Act.

44. Period of Limitation.—An application for judicial review shall be submitted within 21 days of the date on which the sentence was passed by the Coast Guard Court. A petition under section 119 shall be submitted within three months of the date of the order of the Director General on the Judicial Review by the Chief Law Officer of the proceedings of the trial by the Coast Guard Court ;

Provided that the time taken by such person to obtain a copy of the proceedings or the orders of the Director General on the Judicial Review of the proceedings by the Chief Law Officer shall be excluded in calculating the period of 21 days or 3 months as the case may be :

Provided further that an application received after the expiration of the aforesaid period may be entertained by the Director General or the Central Government as the case may be if he or it is satisfied that the delay was due to reasons beyond the control of the applicant.

45. Mode of submitting application and petition.—

(1) An application or a petition may be presented in person or sent by a registered post. It shall be in duplicate and shall be signed by the applicant. It shall state succinctly and clearly all grounds on which the conviction or sentence is sought to be impugned. The applicant should also state whether he desires to be heard in person or through a legal practitioner or an officer of the Coast Guard if the application is under Section 117 of the Act. No personal hearing is required to be given if the petition is under Section 119 of the Act.

(2) An application under Section 117 is to be submitted directly to the Chief Law Officer. A petition under section 119 is to be submitted through the Commander Coast Guard Region in whose command the trial was held. The Commander Coast Guard Region shall forward it to the Director General with his remarks within a period of one month.

(3) A petition against summary award of punishment shall not be entertained. If there are exceptional circumstances warranting interference with the finding or sentence awarded summarily, the case is to be forwarded to the Coast Guard Headquarters through proper channel with full details necessitating the exercise of plenary powers of the Director General or the Central Government as the case may be. As in the case of a petition under section 119 of the Act, the period of limitation shall be 3 months from the date on which the summary punishment was awarded.

Annexure

(Rule 38)

FROM
AT
DATE
TO

ORDER FOR BOARD OF INQUIRY

You are hereby required to assemble in _____ at _____ on _____, the _____ day of _____ 19_____, as a board of inquiry wherein _____ is to be Presiding Officer, and to hold a full and careful investigation into the circumstance of _____.

2. Your report is to be accompanied by the minutes of the evidence taken verbatim and is to contain an expression of your opinion on the merits of the case as disclosed by the evidence; it is also to state fully to whom, if to any person, blame is attributable and to what extent.

3. The questions in the minutes are to be numbered in one series throughout, and the minutes as well as the report, are to be signed by the Presiding Officer and Members of the Board. The name of the witness under examination is to be noted at the head of each page of the report and minutes are to be furnished.

4. Before submitting the minutes and report, you are to see that all papers (or copies of them, if originals are not available) referred to in the proceeding of the Board accompany the original and all copies of the minutes, and that the rules regarding the preparation and submission of the minutes have been fully complied with.

5. Any other matter which arises from the proceeding and which the Board considers shall be brought to the notice of convening officer is to be made the subject of a separate report.

6. You are to be guided by provisions of Chapter VII of the Coast Guard (General) Rules, 1986.

7. _____ is to arrange for the attendance of such witnesses as may be required to be examined by the board.

8. _____ is to arrange for the protection during the inquiry of a confidential stenographer and for provisions of the necessary stationery.

9. All relevant papers are herewith handed to the Presiding Officer of the Board who is to return them with the minutes in due courses.

Signature of convening Officer